Some R&D activities are in progress in Central Power Research Institute at Bangalore for developing the wind mill technology.

(b) A joint project has been undertaken with Federal Republic of Germany for setting up a 10 KW experimental solar power plant at Indan Institute of Technology, Madras. Indian Engineers and Scientists are also keeping in touch with the developments in the field of new energy sources in other parts of the world through participation in international coferences and seminars, exchange of information, etc.

केन्द्रीय हिन्दी समिति

1949. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी नियुक्ति का आधार क्या था ; और

(ख) क्या उसमें संसद सदस्यों को भी लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) केन्द्रीय हिन्दी समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत किए गए हैं :

1. श्री सुधाकर पांडेय
2. डा० मलिक मोहम्मद
3. श्री गंगा शरण सिंह
4. डा० रघुबीर शरण सिंह
5. श्री पी० वी० नरसिंह राव

केन्द्रीय हिन्दी समिति में उन गैर-सरकारी व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार या जन-सेवी हों अथवा अखिल भारतीय स्तर की हिन्दी सेवी संस्थाओं से सम्बद्ध हो और सरकार की राय में, सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग, विकास और प्रसार बढ़ाने में योगदान दे सकते हों ।

(ख) जी हां, श्री पी० वी० नरसिंह राव लोक सभा के सदस्य हैं ।

'समाचार भारती' की शेयर पूंजी

1950. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'समाचार भारती' की शेयर पूंजी प्रेस ट्रस्ट तथा यूनाइटेड न्यूज की पूंजी से कई गुनी थी ; और

(ख) क्या आपातकाल की उदघोषणा से पूर्व ही इसकी समस्त पूंजी समाप्त हो चुकी थी और इस संस्था ने अपने राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण के लिए स्वंय ही सरकार को लिखा था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) : जी, हां ।

(ख) 'समाचार भारती' के 31-12 75 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार कुल हानि 26,38,253 रुपए थी और 31-12-74 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार 25,34,398 रुपए थी ।

समाचार एजेन्सी द्वारा अपने राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के लिए लिखे जाने के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं